

दिनांक: 06.07.2024

समय : 09:00 ए.एम.

प्रादेशिक समाचार
आकाशवाणी जयपुर-अजमेर

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 36 वीरता पुरस्कार प्रदान किए-प्रदेश के दो वीरों को मरणोपरांत शौर्यचक्र दिया गया।
- एक जुलाई से लागू नए तीन आपराधिक कानूनों के तहत प्रदेश में डिजिटल साक्ष्यों को क्लाउड पर स्टोर करने के लिए 'ई-साक्ष्य एप' लॉन्च।
- विश्व पशु जन्य रोग दिवस आज-प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों में बीमारियों से बचाव के लिए जागरुकता कार्यक्रम आयोजित।
- प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर बरसात हुई-आज भी ज्यादातर जगहों पर बारिश की संभावना।

.....

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के पुलिसकर्मियों को 36 वीरता पुरस्कार प्रदान किए। कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में ये पुरस्कार दिये गये। इनमें दस कीर्ति चक्र और 26 शौर्य चक्र शामिल हैं। सात-सात कर्मियों को मरणोपरांत कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। इन्हें विशिष्ट वीरता, अदम्य साहस और कर्तव्य के लिए समर्पण प्रदर्शित करने के लिए सम्मानित किया गया। समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। प्रदेश के वीर मेजर मुस्तफा बोहरा और वीर मेजर विकास भांभू को भी मरणोपरांत शौर्यचक्र दिया गया। राष्ट्रपति ने वीरता पुरस्कार शहीद मेजर मुस्तफा की माता फातेमा और पिता जकीउद्दीन बोहरा को दिया। वहीं हनुमानगढ़ के रामपुरा गांव के निवासी शहीद मेजर विकास भांभू की धर्मपत्नी श्रेया चौधरी और माता सुखवंती ने वीरता पुरस्कार ग्रहण किया।

.....

एक जुलाई से लागू नए तीन आपराधिक कानूनों के तहत प्रदेश में डिजिटल साक्ष्यों को क्लाउड पर स्टोर करने के लिए 'ई-साक्ष्य एप' बनाया गया है। राजस्थान पुलिस की पहल पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा तैयार किये गए इस एप को कल लॉन्च किया गया। पुलिस महानिदेशक, साइबर अपराध और एससीआरबी हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि इस एप को अनुसंधान अधिकारी अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर घटना से संबंधित साक्ष्यों को डिजिटल फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकेंगे। सभी प्रकार के सर्च और सीजर की वीडियोग्राफी भी इस एप के माध्यम से की जा सकेगी। वहीं इस एप पर संकलित साक्ष्यों को सीधे 'क्लाउड' पर डाल दिया जाएगा।

.....

देश में चलाये जा रहे सम्पूर्णता अभियान के तहत प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। जिला और ब्लॉक स्तर पर होने वाले कार्यक्रमों में कल चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा ब्लॉक में अभियान की शुरुआत हुई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर राकेश कुमार ने अभियान की मशाल निम्बाहेड़ा पंचायत समिति के विकास अधिकारी विशाल सीपा को सौंपी। इस अवसर पर सम्पूर्णता की शपथ भी दिलवाई गयी। इस दौरान महिला और बाल विकास विभाग की और से स्टॉल लगाकर लोगों को जागरुक किया गया। इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम और नुककड़ नाटक भी आयोजित किये गये। गौरतलब है कि स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, मृदा और सामाजिक विकास के छह सूचकांकों का शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की गयी है।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोटा और बूंदी जिलों के दौरे पर रहेंगे। दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद श्री बिरला का उनके संसदीय क्षेत्र का ये पहला दौरा है। उनके आगमन पर हिंडौली कस्बे में पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत का कार्यक्रम रखा है। दोपहर में उनका बूंदी और तालेड़ा में अभिनंदन किया जाएगा। इसके बाद श्री बिरला का शाम को कोटा में रोड़ शो का कार्यक्रम है।

नीट-पीजी प्रवेश परीक्षा 2024, 11 अगस्त को आयोजित की जाएगी। दो पारी में होने वाली इस परीक्षा का संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। गौरतलब है कि परीक्षा को निर्धारित तिथि से एक दिन पहले पिछले महीने स्थगित कर दिया गया था।

कोटा में सभी कोचिंग संस्थानों की ओर से नये विद्यार्थियों को प्रवेश देते समय एक यूनिक आईडी दी जाएगी। इसमें हर कोचिंग विद्यार्थी की विशेष पहचान रहेगी। जिला कलेक्टर डॉ. रविन्द्र गोस्वामी ने शहर में आत्महत्या की घटनाओं को देखते हुए कल कोचिंग संस्थानों, हॉस्टल और पीजी प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। जिला कलेक्टर ने बताया कि इसके लिये कोचिंग संस्थानों को 15 जुलाई तक मैकेनिज्म तैयार करना होगा। बैठक में नोडल अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों ने भी भाग लिया। उन्होंने कहा कि कोचिंग कक्षा में प्रतिदिन उपस्थिति का प्रभावी सिस्टम चाहिए। किसी विद्यार्थी के लगातार तीन दिन कक्षा में नहीं आने पर संस्थान को कारणों का पता लगाना होगा। किसी तरह की आशंका होने पर जिला प्रशासन और पुलिस को सूचित किया जाए, ताकि समय रहते आवश्यक कदम उठाए जा सकें।

आज विश्व पशु जन्य रोग दिवस है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य जानवरों से इंसानों में और इंसानों से जानवरों में फैलने वाली बीमारियों के बारे में लोगों को जागरुक करना है। यह रोग संक्रमित जानवर के दूषित मांस, जानवरों की लार, रक्त, मूत्र व बलगम के जरिए फैल सकते हैं। इनमें रेबीज़, स्क्रब टायफस, एवियन इनफ्लुएंजा, जापानी इन्सेफेलाइटिसिस जैसी बीमारियां शामिल हैं। इस अवसर पर प्रदेशभर में विभिन्न स्थानों पर जागरुकता कार्यक्रम आयोजित कर पशु जन्य रोगों से बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं।

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय-आरटीयू कोटा का आज 13वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा है। राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र इसमें शिरकत करेंगे। और ब्यौरा हमारे कोटा संवाददाता से -

प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर कल बरसात हुई। बारां में दिनभर रुक-रुक कर बरसात होती रही। भीलवाड़ा में कल देर शाम रिमझिम बारिश हुई। कोटपूतली-बहरोड़ में बरसात का दौर चला। इससे निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गयी। इससे यातायात भी बाधित रहा। जोधपुर में शाम को तेज हवाओं के साथ वर्षा हुई। बीकानेर में तेज हवा चलने से बिजली के खंभे गिर गये, जिससे बिजली आपूर्ति बाधित रही। मौसम विभाग के अनुसार आज कोटा, बारां और झालावाड़ जिलों में तेज हवा चलने और बारिश की संभावना है। वहीं टोंक, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, जयपुर और दौसा जिलों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं।

केन्द्र सरकार ने रसोई में सुरक्षा, गुणवत्ता और दक्षता बढ़ाने के लिए स्टेनलेस स्टील और एल्यूमीनियम के बर्तनों को भारतीय मानक ब्यूरो-बीआईएस के अनुरूप अनिवार्य कर दिया है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के आदेश के अनुसार ऐसे बर्तनों के लिए आईएसआई चिन्ह अनिवार्य होगा। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा है कि इस आदेश का अनुपालन नहीं करना दंडनीय है। हाल ही में बीआईएस ने रसोई की आवश्यक वस्तुओं सहित मानकों की एक श्रृंखला तैयार की है।

संचार मंत्रालय ने देश में हाल ही में मोबाइल सेवा शुल्क में बढ़ोतरी के बारे में कहा है सरकार ग्राहकों के हितों की रक्षा करने, नई तकनीकों में निवेश के साथ व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान दे रही है। मंत्रालय ने कहा कि मोबाइल सेवा बाजार, मांग और आपूर्ति के माध्यम से संचालित होता है। हाल ही में, तीन निजी कंपनियों और एक सार्वजनिक मोबाइल कंपनी ने सेवा शुल्क बढ़ाया है। मंत्रालय

ने कहा कि सरकार की नीतियों और नियामक ढांचे के परिणामस्वरूप भारत में मोबाइल ग्राहकों के लिए लागत सबसे कम है।

.....